**जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में स्कूलों और कालेजों का खोलना**

695. **श्री कृष्ण चन्द्र पान्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कूल और डिग्री कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोगों के बच्चे कम लागत पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले का सेमियाखान ब्लाक बहुत पिछड़ा हुआ है और डिग्री कालेज वहां से काफ़ी दूरी पर है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) :** (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों, विशेष कर रक्षा कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां पर इस प्रकार के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होते है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

देश के किसी भी भाग में डिग्री कालेज स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है । अतः बस्ती जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई डिग्री कालेज खोले जाने का प्रश्न ही नही उठता ।

**सामान्य जनता को कुकिंग गैस उपलब्ध कराना**

696. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सामान्य जनता को कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** (क) जी, हां ।

(ख) देश में सरकार का खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को बढ़ाने का विचार है जो 1980-81 के लगभग निम्नलिखित परियोजनाओं के चालू होने से सम्भव होगी :

(1) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पैट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधायें ;

(2) मथुरा शोधनशाला ;

(3) कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन सुविधायें; और

(4) बोंगईगांव शोधनशाला की कोकर यूनिट ।

इसी बीच, शोधनशालाओं में तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने के अतिरिक्त, सरकार का खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए यथा सम्भव इसके आयात करने की योजना है ।

**अनुसूचित जातियों/जनजातियों को गैस और पेट्रोलियम उत्पाद एजेन्सीयों का आवंटन**

697. **श्री राम लाल राही :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा 1978-79 और 1979-80 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगो के लिए गैस और पेट्रोलियम व्यापार में आरक्षणा के लिए कुछ स्थानों का चयन किया गया था और आवेदन आमंत्रित किए गए थे और तदनुसार साक्षात्कार भी किया गया था ;

(ख) यदि हा, तो उनके लिए विभिन्न स्थानों पर लिए गए आरक्षण के आधार पर चुने गए इन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने में अब किस कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है , और

(ग) क्या, सरकार इन लोगों को, दिल्ली लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि जैसे स्थानों पर गैस एजेंसी लेने के अवसर प्रदान करने के लिए तत्काल कोई निर्णय करेगी ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली वर्तमान नीति के अनुसार सभी प्रकार की एजेन्सियों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिया जाना होता है । खाना पकाने वाली गैस की एजेन्सियों को छोड़कर, इन समुदायों को दी जाने वाली डीलरशिपों के स्थान पूर्वनिर्धारित नहीं होते । जहां तक खाना पकाने वाली गैस की एजेन्सियों का सम्बन्ध है, वर्ष 1978-79 के लिए आयोजित 87 एजेन्सियों में से 24 एजेन्सियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं जिनके लिए स्थल का निर्धारण 15-5-1978 को तत्कालीन मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार किया गया था । इसी प्रकार तेल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां देने के लिए वर्ष 1979-80

के लिए योजना तैयार की गई है और निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार तेल कम्पनियां कार्रवाई कर रही हैं।

परन्तु उत्पाद की उपलब्धता न होने के कारण खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियों का चालू किया जाना स्थगित रखा गया है। जब और गैस उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा, पहले से दी गई एजेन्सियों को चालू करने के लिए तेल कम्पनियां आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

**छपरा टेलीफोन एक्सचेंज (बिहार) की खराब स्थिति**

698. **प्रो० सत्यदेव सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छपरा टेलीफोन एक्सचेंज (बिहार) की बिगड़ती स्थिति के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और

(ग) सरकार ने इस बारे मे क्या कार्यवाही की है ?

**संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) 100 लाइनें और बढ़ा कर एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से यातायात को और अधिक दक्षतापूर्वक निपटाने में सहायता मिलेगी।

**Supply of Petroleum Products to States**

699. **SHRI CHANDRAJIT YADAV**: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS be pleased to stae:

(a) how much diesel and kerosene oil had been supplied to different States during last two months;

(b) how much was the demand from these States and what per cent of their demand has been fulfilled; and

(c) whether it is a fact that Government of India is seriously thinking to increase the prices of Petroleum, diesel and kerosene oil?

**THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI VEERENDRA PATIL)**: (a) A statement indicating the provisional sales figures of High Speed Diesel and kerosene in different States and Union Territories for January and February, 1980 is attached.

(b) The State Governments had been asking for additional allocations from time to time. It is not possible to indicate the percentage of demand that has been fulfilled.

(c) Successive and steep increases in the prices of imported crude oil and petroleum products from the last quarter of 1979 had led to a phenomenal increase in the import bill. Increases in the domestic prices of petroleum products cannot be ruled out.

**Statement**

*State-wise High Speed Diesel oil and Kerosene oil sales) Provisional) in the months of January and February, 1980.*

*(Figures in Metric tonnes)*

| States/Union Territories | High Speed Diesel oil | | Kerosene | |
|---|---|---|---|---|
| | January'80 (Prov.) | February'80 (Prov.) | January'80 (Prov.) | February'80 (Prov.) |
| 1. Andhra Pradesh | 61236 | 64432 | 28405 | 27594 |
| 2. Arunachal Pradesh | 349 | 335 | 226 | 270 |
| 3. Assam | 8304 | 6066 | 4444 | 2802 |